sanctioned other than those on the recommendations of MPs have been held in abeyance.

(b) 2199 OBs/Work orders in Delhi and 1883 OBg/work orders in Bombay have been issued in the month of June, 1991.

(c) For a review of the position in view of some complaints.

(d) The connection sanctioned on the recommendations of MPs are given priority.

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

2304. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम पंचायतों को टेलीफोन उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ कर दी गयी है और इस क्षेत्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और सुल्तानपुर में तथा गुजरात में भी ग्राम पंचायतों में स्थापित किये गये टेलीफोनों का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पुरानी पद्धति को फिर से शुरू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं, जिसमें गैर एस०टी०डी० स्थानों/गांवों से बुक की जाने वाली ट्रंक कालों को कुछ घंटों के दौरान रियायत दी जाती थी ; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये की गई ट्रंक कालों में रियायती दरों को पुनः चालू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां, 30–11–91 तक कुल 228926 ग्राम पंचायतों में से 48922 को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और गुजरात की ग्राम पंचायतों में 31–11–91 तक संस्थापित टेलीफोनों का जिलेवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। नीचे देखिए

(ग) और (घ) काल मिलने के समय पर आधारित ट्रंक कालों को दी जाने वाली सामान्य छूट के अलावा ग्राम पंचायत टेलीफोन से ली जाने वाली कालों के प्रभारों में 50० की और छूट दी जाती है ।

विवरण

राज्य	जिला	30–11–1991 तक टेलीफोन सुविधा वाली ग्राम पंचायतें
उत्तर प्रदेश	1. गाजीपुर	61
	2. जौनपुर	65
	3. सुल्तानपुर	269
	4. आजमगढ़	60
	5. मऊ	72
		527

1	2	3
गुजरात	1. अहमदाबाद	145
	2. अम्बरेली	150
	3. बनासकांठा	150
	4. भावनगर	153
	5. भड़ौंच	126
	6. जाम नगर	145
	7. उन्जागढ़	221
	8. खेड़ा	226
	9. भुज	186
	10. मसाना	302
	11. पंचमहल	140
	12. राजकोट	189
	13. साबर-कांठा	176
	14. सुन्दरनगर	140
	15. सूरत	152
	16. बड़ौदा	107
	17. बालसर	158
		2875

News item captioned "Telecom Sector in Doldrums'

2305. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the news-item which appeared in the Hindustan Times, New Delhi on 21st September 1991, under the caption 'Telecom Sector in doldrums'; and

(b) if so, what is Government's reaction in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) It is not correct to say that the Telecom Sector is suffering from benign neglect. Chairman Telecom Commission has since been appointed and is functioning. It is also not correct that the industrial policy announcement came as a shock to the Communication Ministry or that it sounds the death knell of ITI.

Terms and Conditions of Bids for Share of Telecom Market

2306. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have set November 15, 1991 as the deadline for seven multinational Telecom companies to make their bids for a share of the Indian telecom market as per the news item entitled "MNCs await Government terms on telecom bids", which appeared in the Hindustan Times, dated November 9, 1991;

(b) whether Government have issued any formal communication to those seven companies regarding terms and conditions of the bids;

(c) if so, what are the details thereof and what was the response from those companies; and

(d) if answer to part (b) above bo in negative, what are the reasons therefor?